We have seen, Sir, evidence of Rohingya involvement in the blast in Bodh Gaya, the most sacred Buddhist site, and we have seen, in October, 2016, that one of the two militants killed in an encounter in Jammu and Kashmir, turned out to be from Myanmar.

To my mind, Sir, it is something which is a pressing matter, which goes beyond the humanitarian aspect. We are all very concerned when there are humanitarian issues. But this is an issue which concerns the national security and which is more serious because these Rohingyas have been flaunting Voter Cards; they have been flaunting Aadhaar Cards in Jammu; it is only when they tried to register themselves as State Subjects that the issue came to the fore and assumed great importance.

So, I would urge the Government to take this matter very, very seriously.

Concern over the scarcity of life saving drugs in hospitals after implementation of GST

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, 1 जुलाई, 2017 से देश में नई कर प्रणाली लागू हुई है। मेरी पार्टी जनता दल (युनाइटेड) ने इसका समर्थन किया है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद देश के विभिन्न अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति नहीं हो रही है। पूर्व के राज्यों, खासकर बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एवं झारखंड के अस्पतालों में दवाओं की भारी किल्लत हो गई है और इससे नाराज़ मेडिकल कॉलेज कर्मचारी एसोसिएशन ने अंदोलन की भी चेतावनी दी है।

महोदय, इन राज्यों के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में गुणात्मक रूप से वृद्धि होने के बावजूद भी इनके बजट में कटौती कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की कॉंट्रेक्ट लिस्ट में अभी मात्र 1100 दवाएँ ही शामिल हैं, जबकि गत वर्ष तक लगभग 4000 दवाएं इसमें शामिल थीं, खासकर जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत तो पूर्व के सभी राज्यों मे है। बजट में राशि कम होने और लिस्ट में दवाएं कम होने से अस्पताल प्रशासन दवाएं खरीद नहीं पा रही है, अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि देश के सभी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): सर, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री हरिवंश (बिहार): सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, there is a Short Duration Discussion notice given by many Members on how, after demonetisation and GST, prices have gone up. Please consider it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. We will consider it.

Concern over the poor quality of food served in trains

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इस सदन के संज्ञान में एक गंभीर मसला लाना चाहता हूं। रेलवे भारत का सबसे बड़ा पब्लिक कैरियर है। अढ़ाई करोड़ लोग हर रोज़ इससे सफर करते हैं। अभी सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसके पहले से एक शिकायत की जा रही थी कि रेलवे का खाना अच्छा नहीं होता है और सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया कि जनता की जो शिकायत थी, वह बिल्कुल सही थी। वह खाना ऐसे पानी में बनाया जाता है, जो अशुद्ध होता है। वे गंदे पानी में खाने को पकाते हैं और जो खाना बच जाता है, दूसरे दिन वही खाना गर्म करके पब्लिक को दे देते हैं। मान्यवर, वह सब खाना खुला रहता है। उसके ऊपर तिलचट्टे, चूहे और अन्य कीड़े घूमते रहते हैं और उसे खाते रहते हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। रेलवे में लगभग ढाई करोड़ आम आदमी ज्यादातर सफर करते हैं। वे हवाई जहाज से सफर नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, इस सरकार ने रेलवे का जितना किराया बढ़ाया है, उतना पिछले 70 सालों में कभी नहीं बढ़ा। इसकी दो casualties हैं। एक तो खाना गन्दा, खराब, घटिया और sub-standard होता है और दूसरे सेफ्टी का मामला है। इस सरकार के समय में जितने एक्सीडेंट्स हुए और जितने लोग मारे गए, उतने कभी नहीं मारे गए।

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि खाने की क्वालिटी को ठीक कराएं और उसे कम से कम शुद्ध पानी में तो बनाया जाए। आम आदमी रेल में सफर करता है, वह रेलवे का खाना खाकर बीमार पड़ जाता है। उसे खाने से बीमारी हो जाती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सरकार को और रेल मंत्री को निर्देश दें कि खाने की क्वालिटी इम्प्रूव कराएं और कम से कम casualties हों।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a very serious issue. Names of all those who associated themselves with the matter will be added, including Shri Kiranmay Nanda, Shri Motilal Vora. I think, the Government should take serious note of it because the foods are very sub-standard.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI) : Okay, Sir.